सिफारिशे की गई थी उन मे एक यह थी कि हिन्दुस्तान मे भैस का दूध और गाय का दूध एक कीमत पर बेचा जाय । तो मै यह मालूम करना चाहता हूं कि इस सिफारिश को सरकार ने कहा तक मंजूर किया है ?

श्री शाहनवाज खां : वह तो खरीददारों के उपर है कि वे किस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है ?

श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या श्रीमान, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी आप ने फरमाया कि यह गोसवर्धन कौसिल बहुत अच्छा काम कर रही है तो इसका अच्छा काम दूध न होने से आका जा रहा है या कोई ऐसे मेज़र्स है जिस से यह आका जा रहा है कि अच्छा काम हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : यह कमेटी इस तरह से अच्छा काम कर रही है कि जिन इलाको से गाय का दूध नही मिल ता था अब उन इलाकों से गाय का दूध मुहय्या करने का इन्तजाम कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर बिकानेर का इलाका है जहा पर अच्छे किस्म का गाय का दूध मिलता है वहा पर गाय का दूध लेने का उन्होने इन्तजाम किया है और ३०० मन दूध रोजाना बिकानेर के इलाके से लाया जा रहा है । यह जो काम है बहुत अच्छा काम है ।

कृषको का ऋण भार

*५७१. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ३१ मार्च, १९६४ तक गत तीन वर्षों मे कृषको का ऋण भार कितना बढा है तथा उनको जो व्याज देना पड़ता है उसकी औसत दर क्या है ; और

(ख) इस ऋणभार को कम करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

†[INDEBTEDNESS OF FARMERS

*571. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION be pleased to state:

(a) to what extent the indebtedness of farmers increased during the last three years, upto 31st March, 1964, and what is the average rate of interest which they have to pay; and

(b) what arrangements are being made by Government to reduce the indebtedness?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI B. S. MURTHY): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

On the basis of the All India Rural Debt and Investment Survey carried out by the Reserve Bank of India, the cash borrowings of all cultivating households during the period 1st July, 1961 to 30th June, 1962 are provisionally estimated at about Rs. 1,030 crores. In the absence of any further survey it is not possible to state whether indebtedness has increased since that year.

In respect of borrowings from agricultural credit cooperatives, the rate of interest ranged from 6¼% to 9¾% during 1961-62. The rates of interest on borrowings from other sources are not known.

Government have taken measures for provision of increased credit and marketing facilities through cooperatives, so that production increases and the farmer gets a fair price.

‡[**सामुदायिक विकास और सहकारिता: मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति)** (क) व (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

† [ ] English translation.
‡ [ ] Hindi translation.

विवरण

(क) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा किए गए अखिल भारतीय ग्राम-ऋण और निवेश सर्वेक्षण के आधार पर १ जुलाई, १९६१ से ३० जन, १९६२ तक की अवधि मे सभी खेतीहर परिवारों के नकद ऋणो की राशि अस्थायी रूप से लगभग १०३० करोड़ रुपये आकी जाती है । आगे और कोई सर्वेक्षण न होने के कारण यह कहना सम्भव नही है कि क्या उस वर्ष के बाद ऋण भार बढ़ा है ।

कृषि ऋण सहकारी समितियो के लिये जाने वाले ऋणों पर १९६१–६२ मे ब्याज की दर ६ १।४ प्रतिशत से ९ ३।८ प्रतिशत के बीच थी । अन्य स्रोतों से लिये जाने वाले ऋणो की ब्याज की दरें मालूम नही है ।

(ख) सरकार ने सहकारी समितियो के माध्यम से अधिक ऋण और विपणन की सुविधाओ की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाए है, ताकि उत्पादन बढ़े और किसान को उचित मल्य मिले ।]

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगे कि रिजर्व बैंक किन किन वर्षो मे यह सर्वेक्षण करती है और क्य इन सर्वेक्षणो में कर्जदारो से यह बात पूछी जाती है कि आपने यह कर्ज कितने सूद पर लिया ?

SHRI B. S. MURTHY: The Reserve Bank had undertaken a survey in 1951 and 75 districts had been covered. Again after ten years in 1961 it has undertaken a survey and in this 1,889 villages have been covered. In this survey it is trying to find out rural indebtedness, rural borrowings, capital formations, etc., by meeting each rural family, both cultivation and non-cultivation families.

श्री भागवत नारायण भार्गव : इस विवरण में जो सरकार ने टेबिल पर रखा है , इसमें यह कहा गया है, "सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक ऋण और वितरण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये है ताकि उत्पादन बढ़े और किसान को उचित मूल्य मिले ।" तो मै यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कदम उठाये गये और १७ वर्षों से यह काम चल रहा है, उसके होते हुए क्या कारण है कि उनका कर्जा अब भी बढ़ रहा है ?

SHRI B. S. MURTHY: The hon. Member will be pleased to know that in 1955-56 the co-operative credit was only Rs. 49 crores, whereas it increased in 1962-63 to Rs. 260 crores, and it is hoped that by 1965-66 it will be Rs. 400 crores.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : श्रीमान यह बतलायेगे कि शासन का लक्ष्य कृषको का कर्जा कम करने का है, और उस मे वृद्धि करना है, तो ऐसे कृषको की आमदनी का कितना हिस्सा ब्याज के रूप में चला जाता है ?

SHRI B. S. MURTHY: I think when the Reserve Bank sends its teams for rural survey, all these questions are taken into consideration and full justice is done to find out the rural indebtedness.

SHRI T. V. ANANDAN: Will the hon. Minister be pleased to state whether the rural indebtedness will be increased or reduced if the rate of interest charged against the farmers ranges between 8 and 9·5 per cent?

SHRI S. K. DEY: The rural indebtedness is bound to increase as there is progress in modern technology in agriculture. There is every effort that the State Governments are making to see that credit to the fullest extent is given through the co-operative organisations.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान बतलायेंगे कि बहुत सी सहकार संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला कर्जा भी

अनप्रोडेक्टेटिव कामो के खर्च पर चला जाता है, जिसकी जह से सहकार समितिया अच्छा काय नही कर पाती है, तो इसको रोकने के लिये सरकार कोई व्यवस्था करने की सोच रही है ?

SHRI S K DEY: An evaluation was conducted by the Evaluation Agency of the Planning Commission to see what amount of utilisation there was of co-operative credit for productive purposes, and we found that 70 to 75 per cent of the rural credit was in fact being utilised for actual productive purposes, and the rest was utilised to meet the emergent needs of farmers

MR CHAIRMAN The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

SCHEME FOR REDUCING ELECTION EXPENSES, ETC

*557 SHRI SITARAM JAIPURIA: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Election Commission is preparing a comprehensive scheme with a view to reduce election expenses, eliminate corrupt practices and to speed-up the disposal of election petitions;

(b) if so, what are the details of the scheme, and

(c) by when the scheme would be implemented?

THE MINISTER OF LAW (SHRI A. K SEN): (a) No, Sir

(b) and (c) Do not arise.

NON-SUPPLY OF BUFFALO AND COW MILK BY DELHI MILK SCHEME

*559 SHRI RAM SINGH Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during October 1964, no buffalo or cow milk was supplied to the card holders by the Delhi Milk Scheme; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI C SUBRAMANIAM) (a) and (b) A statement is placed on the table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Delhi Milk Scheme was unable to meet its commitments for the supply of buffalo milk for some days during October, 1964 and toned milk in lieu of buffalo milk was supplied upto 20th October 1964 Supply of toned milk had also to be reduced by about 50 per cent. from 27th September 1964 to 12th October 1964.

Cow milk was supplied to the card holders throughout the month of October, 1964 except on 7th, 23rd and 27th October, 1964 On 24th, 26th, 28th, and 31st October, 1964, a partial supply of cow milk was made.

(b) There has been a shortfall in the quantity of buffalo milk procured by the Delhi Milk Scheme for the following reasons:

(i) There was some agitation among milk suppliers because of procurement of milk by the scheme through Cooperative Societies at the Milk Collection and Chilling Centre at Kithore, Uttar Pradesh.

(ii) The greatly increased price in the Delhi Market of products like cream and ghee which makes it profitable for supplier to divert milk for the manufacture of cream and ghee.

(iii) Unhealthy competition by private purchasers particu-